समय से लेकर अब तक कितनी रुग्ण वस्त्र मिलों का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) अब तक ऐसी कितनी मिलों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया गया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा इन मिलों के अधिग्रहण किये जाने के बाद इसके कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है:

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनमें से कितनी मिलें बंद पड़ी हैं और उन मिलों में कार्यरत ऐसे मजदूरों की संख्या कितनी है जिन्होंने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले ली है और कितने श्रमिक बिना काम तथा वेतन के जीवन निर्वाह कर रहे हैं; उनके लिये अब तक क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) वर्ष 1968 में एन टी सी को निगमित किया गया तथा तब से उसने 125 मिलों का अधिग्रहण किया है। इन में से एक मिल के प्रबन्धन के अधिग्रहण की अवधि 22.6.1988 से आगे नहीं बढ़ाई गई। बाद में पश्चिम बंगाल में 5 मिलों को दो मिलों में मिला दिया गया। इस प्रकार इस समय एन टी सी के अधीन 122 मिलें (107 राष्ट्रीयकृत तथा 15 अधिग्रहित मिलें) हैं। राष्ट्रीयकृत मिलों में ऐसी दो मिलें भी शामिल हैं जिन्हें अधिग्रहण के बाद दुबारा नहीं चलाया गया।

(ख) से (घ) अनेक वर्षों से एन टी सी के अधीन अधिकांश राष्ट्रीयकृत मिलों में अलग-अलग राशियों का निवेश किया गया है ताकि उन्हें चालू रखा जा सके। इन मिलों के अधिग्रहण के समय के तकुओं की तुलना में तकुओं में वृद्धि की गई है। तथापि, कुल मिलों में खर्चीले कारणों को बन्द करने के फलस्वरूप करघों की संख्या में कमी आई है। एन टी सी मिलों को घाटे हो रहे हैं जिनके कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ पुरानी तथा अप्रचलित मशीनें, अपर्याप्त आधुनिकीकरण, कार्यशील पूंजी की जटिल कमी, कम क्षमता उपयोग, उच्च मानव मशीन अनुपात शामिल हैं।

(ङ) एन टी सी अपने वैसी कर्मचारियों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना क्रियान्वित कर रहा है। 28.2.1995 तक 35,716 कामगारों/कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लाभ उठाया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार एन टी सी की कोई भी मिल बन्द नहीं है लेकिन कार्यशील पूंजी की मुख्य कमी के कारण कुछ मिलों में आंशिकपूर्ण रूप से कार्य बन्द है। इसके फलस्वरूप ऐसी मिलों के कामगारों को काम के बिना वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

Criticism on Contracts to MNC's for Power Projects

2361. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that, due to lack of transparency in awarding contracts to MNC's for power projects, sharp criticism has surfaced; and

(b) if so, what are the details of contracts which have come in for criticism?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILA BEN CHEMANBHAI PATEL): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

2362. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को स्वीकृति देने के बाद पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान सरकार को क्रमश: कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनमें कितना पूंजी निवेश अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों में से कई प्रस्तावों को सरकार ने अपनी स्वीकृति भी दे दी थी;

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान वर्षवार कुल कितने प्रस्ताव अनुमोदित किए गए थे तथा उनमें से कितने वास्तव में दिसम्बर, 1994 से क्रियान्वित किए जा रहे हैं; और

(ङ) शेष प्रस्तावों के क्रियान्वयन में विलम्ब के